LOK SABHA DEBATES

(Part I — Proceedings with Questions and Answers)

The House met at Eleven of the Clock

Monday, December 09, 2024 / Agrahayana 18, 1946 (Saka)

HON'BLE SPEAKER

Shri Om Birla

PANEL OF CHAIRPERSONS

Shri Jagdambika Pal

Shri P. C. Mohan

Shrimati Sandhya Ray

Shri Dilip Saikia

Kumari Selja

Shri Raja A.

Dr. Kakoli Ghosh Dastidar

Shri Krishna Prasad Tenneti

Shri Awadhesh Prasad

LOK SABHA DEBATES

PART I – QUESTIONS AND ANSWERS

Monday, December 09, 2024 / Agrahayana 18, 1946 (Saka)

CONTENTS **PAGES**

…	1
WRITTEN ANSWERS TO STARRED QUESTIONS (S.Q. NO. 181 – 200)	2 – 50
WRITTEN ANSWERS TO UNSTARRED QUESTIONS (U.S.Q. NO. 2071 – 2300)	51 – 280

सत्यमेव जयते

LOK SABHA DEBATES

(Part II - Proceedings other than Questions and Answers)

Monday, December 9, 2024 / Agrahayana 18, 1946 (Saka)

LOK SABHA DEBATES

PART II – PROCEEDINGS OTHER THAN QUESTIONS AND ANSWERS

Monday, December 9, 2024 / Agrahayana 18, 1946 (Saka)

C ON T E N T S **P A G E S**

RULING RE: NOTICES OF ADJOURNMENT MOTION	281
PAPERS LAID ON THE TABLE	281 - 304
COMMITTEE ON THE WELFARE OF SCHEDULED CASTES AND SCHEDULED TRIBES	305
Statements	
STANDING COMMITTEE ON RURAL DEVELOPMENT AND PANCHAYATI RAJ	305
Statement	
…	306
MATTERS UNDER RULE 377 – LAID	307 - 19
Shri Parshottambhai Rupala	307
Shrimati D. K. Aruna	308
Shri Jagdambika Pal	308
Shri Rajiv Pratap Rudy	309
Dr. Jayanta Kumar Roy	309
Shrimati Malvika Devi	310
Shri Rodmal Nagar	310
Shri Ashok Kumar Rawat	311
Dr. Bhola Singh	311
Shri Ramesh Awasthi	312
Shri Hibi Eden	312

Prof. Varsha Eknath Gaikwad	313
Shri Balwant Baswant Wankhade	313
Shri Robert Bruce C.	314
Md. Rakibul Hussain	314
Shri Sanatan Pandey	315
Shri Aditya Yadav	315
Shri Kirti Azad	316
Shri Malaiyarasan D.	316
Shri Lavu Srikrishna Devarayalu	317
Shri Dileshwar Kamait	317
Shrimati Supriya Sule	318
Shri Maddila Gurumoorthy	318
Shri Sudhakar Singh	319
Shri N. K. Premchandaran	319

RAILWAYS (AMENDMENT) BILL **320**
(Contd. - Inconclusive)

Shri Ashwini Vaishnaw **320**
(Speech not finished)

… **321**

(1100/GG/NKL)
1100 बजे

(माननीय अध्यक्ष पीठासीन हुए)

… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्य, प्रश्न काल महत्वपूर्ण समय होता है। मेरा आपसे आग्रह है कि यह सदन का समय होता है।

… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्य अपने स्थानों पर बैठें और प्रश्न काल को चलने दें।

… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : क्या आप प्रश्न काल नहीं चलने देना चाहते हैं? आप सदन नहीं चलाना चाहते हैं?

… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : मेरा आपसे आग्रह है कि प्रश्न काल में किसी विषय को नहीं उठाया जाता है।

… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : मैं पुन: आपसे आग्रह कर रहा हूँ कि प्रश्न काल सबसे महत्वपूर्ण समय होता है।

… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : देश चाहता है कि सदन चले, सदन की कार्यवाही चले।

… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप सदन में गतिरोध पैदा कर रहे हैं।

… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप सदन नहीं चलाना चाहते हैं?

… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप सदन नहीं चलाना चाहते हैं?

… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : सदन की कार्यवाही 12 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

… (व्यवधान)

1104 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा बारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

(1200/MY/VR)

लोक सभा बारह बजे पुनः समवेत् हुई।

(श्रीमती संध्या राय पीठासीन हुईं)

...(व्यवधान)

स्थगन प्रस्ताव की सूचनाओं के बारे में विनिर्णय

1200 बजे

माननीय सभापति : माननीय सदस्यगण, मुझे कुछ विषयों पर स्थगन प्रस्ताव के नोटिसेज प्राप्त हुए हैं। माननीय अध्यक्ष जी ने स्थगन प्रस्ताव के किसी भी नोटिस के लिए स्वीकृति नहीं दी है।

... (व्यवधान)

1200 बजे

(इस समय श्री बी. मणिक्कम टैगोर और कुछ अन्य माननीय सदस्य आकर पटल के निकट खड़े हो गए।)

... (व्यवधान)

सभा पटल पर रखे गए पत्र

1201 बजे

माननीय सभापति : अब पत्र सभा पटल पर रखे जाएंगे। आइटम नम्बर – 2.

श्री जयंत चौधरी जी।

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF SKILL DEVELOPMENT AND ENTREPRENEURSHIP; AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF EDUCATION (SHRI JAYANT CHAUDHARY): Madam, I beg to lay on the Table:-

(1) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Lakshadweep Samgra Shiksha State Mission Authority, Kavaratti, for the year 2022-2023 alongwith audited accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Lakshadweep Samgra Shiksha State Mission Authority, Kavaratti, for the year 2022-2023.

(2) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (1) above.

(3) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Uttarakhand Samgra Shiksha, Dehradun, for the year 2023-2024.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Uttarakhand Samgra Shiksha, Dehradun, for the year 2023-2024.

(4) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (3) above.

(5) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Samgra Shiksha, Dadra and Nagar Haveli and Daman and Dui, Daman, for the year 2022-2023, alongwith audited accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Samgra Shiksha, Dadra and Nagar Haveli and Daman and Dui, Daman, for the year 2022-2023.

(6) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (5) above.

(7) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Samgra Shiksha Chandigarh, Chandigarh, for the year 2023-2024, alongwith audited accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Samgra Shiksha Chandigarh, Chandigarh, for the year 2023-2024.

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पंकज चौधरी): सभापति महोदया, मैं निम्नलिखित प्रस्ताव सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 की धारा 31 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (किसी निर्गम के बैंकर) (संशोधन) विनियम, 2024 जो दिनांक 20 नवम्बर, 2024 के भारत के राजपत्र में

अधिसूचना संख्या सेबी-एलएडी-एनआरओ/जीएन/2024/211 में प्रकाशित हुए थे।

(दो) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (विदेशी उद्यम पूँजी निवेशक) (संशोधन) विनियम, 2024 जो दिनांक 5 सितंबर, 2024 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सेबी-एलएडी-एनआरओ/जीएन/2024/203 में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (म्यूचुअल फंड) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2024 जो दिनांक 2 अगस्त, 2024 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सेबी-एलएडी-एनआरओ/जीएन/2024/197 में प्रकाशित हुए थे।

(चार) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (वैकल्पिक निवेश निधि) (चौथा संशोधन) विनियम, 2024 जो दिनांक 6 अगस्त, 2024 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सेबी-एलएडी-एनआरओ/जीएन/2024/198 में प्रकाशित हुए थे।

(पाँच) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (गैर-परिवर्तनीय प्रतिभूतियों का निर्गम और सूचीकरण) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2024, जो दिनांक 18 सितम्बर, 2024 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सेबी-एलएडी-एनआरओ/जीएन/2024/205 में प्रकाशित हुए थे।

(छह) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (इक्विटी शेयरों की डीलिस्टिंग) (संशोधन) विनियम, 2024 जो दिनांक 25 सितम्बर, 2024 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सेबी-एलएडी-एनआरओ/जीएन/2024/206 में प्रकाशित हुए थे।

(सात) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (अवसंरचना निवेश ट्रस्ट) (तीसरा संशोधन) विनियम, 2024 जो दिनांक 27 सितम्बर, 2024 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सेबी -एलएडी-एनआरओ/जीएन/2024/207 में प्रकाशित हुए थे।

(आठ) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (रियल एस्टेट निवेश ट्रस्ट) (तीसरा संशोधन) विनियम, 2024 जो दिनांक 27 सितंबर, 2024 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सेबी-एलएडी-एनआरओ/जीएन/2024/208 में प्रकाशित हुए थे।

(2) सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :-

(एक) सा.का.नि. 3485(अ) जो दिनांक 14 अगस्त, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय दिनांक 3 अगस्त, 2001 की

अधिसूचना संख्या 36/2001-सीमाशुल्क(एनटी) में संशोधन करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) का.आ.3720(अ) जो दिनांक 30 अगस्त, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसका आशय दिनांक 3 अगस्त, 2001 की अधिसूचना संख्या 36/2001-सीमाशुल्क (एनटी) में संशोधन करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) का.आ.3945(अ) जो दिनांक 13 सितंबर, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसका आशय दिनांक 3 अगस्त, 2001 की अधिसूचना संख्या 36/2001-सीमाशुल्क (एनटी) में संशोधन करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चार) का.आ.4239(अ) जो दिनांक 26 सितंबर, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसका आशय दिनांक 3 अगस्त, 2001 की अधिसूचना संख्या 36/2001-सीमाशुल्क (एनटी) में संशोधन करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पाँच) का.आ.4267(अ) जो दिनांक 30 सितंबर, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसका आशय दिनांक 3 अगस्त, 2001 की अधिसूचना संख्या 36/2001-सीमाशुल्क (एनटी) में संशोधन करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(छह) सा.का.नि.4535(अ) जो दिनांक 15 अक्तूबर, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका दिनांक आशय 3 अगस्त, 2001 की अधिसूचना संख्या 36/2001-सीमाशुल्क (एनटी) में संशोधन करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सात) सा.का.नि.4642(अ) जो दिनांक 23 अक्तूबर, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय दिनांक 3 अगस्त, 2001 की अधिसूचना संख्या 36/2001-सीमाशुल्क (एनटी) में संशोधन करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(आठ) सा.का.नि.4777(अ) जो दिनांक 30 अक्तूबर, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय दिनांक 3 अगस्त, 2001 की अधिसूचना संख्या 36/2001-सीमाशुल्क (एनटी) में संशोधन करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(नौ) सा.का.नि.4906(अ) जो दिनांक 12 नवम्बर, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय दिनांक 3 अगस्त, 2001 की अधिसूचना संख्या 36/2001-सीमाशुल्क (एनटी) में संशोधन करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दस) सा.का.नि.4919(अ) जो दिनांक 13 नवम्बर, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय दिनांक 3 अगस्त, 2001 की अधिसूचना संख्या 36/2001-सीमाशुल्क (एनटी) में संशोधन करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(ग्यारह) सा.का.नि.4931(अ) जो दिनांक 14 नवम्बर, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय 3 अगस्त, 2001 की अधिसूचना संख्या 36/2001-सीमाशुल्क (एनटी) में संशोधन करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(बारह) दिनांक 18 अक्तूबर, 2024 का आदेश संख्या एफ. सं. 462/07/2024-सीमाशुल्क V (2024 का तदर्थ छूट आदेश संख्या 06) जो जिम्बाब्वे, मलावी, जाम्बिया और नामीबिया को खाद्यान्न के रूप में मानवीय सहायता के संबंध में सीमाशुल्क के भुगतान से तदर्थ छूट प्रदान करने के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(3) सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 9क की उप-धारा (7) के अंतर्गत सा.का.नि.725(अ) जो दिनांक 22 नवम्बर, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे, जिनका आशय दिनांक 27 मार्च, 2021 की अधिसूचना संख्या 18/2021-सीमाशुल्क (एडीडी) में संशोधन करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(4) केंद्रीय उत्पादशुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 38 की उप-धारा (2) के अंतर्गत सा.का.नि.716(अ) जो दिनांक 19 नवम्बर, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे, जिनका आशय दिनांक 30 जून, 2017 की अधिसूचना संख्या 11/2017-केन्द्रीय उत्पादशुल्क में संशोधन करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(5) शेयर बाजार घोटाला और उससे संबंधित मामलों संबंधी संयुक्त संसदीय समिति-दिसम्बर 2024 की सिफारिशों के अनुसरण में की-गई-कार्रवाई संबंधी 43वें प्रगति प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) (एक) इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनोमिक ग्रोथ, दिल्ली के वर्ष 2023-2024 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनोमिक ग्रोथ, दिल्ली के वर्ष 2023-2024 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(7) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा 1(ख) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :-

(एक) इंडिया इन्फ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2023-2024 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा ।

(दो) इंडिया इन्फ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2023-2024 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां।

... (व्यवधान)

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES; AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT (SUSHRI SHOBHA KARANDLAJE): Madam, I beg to lay on the Table:-

(1) A copy each of the following Notifications (Hindi and English versions) under sub-section (3) of Section 40 of the Industrial Disputes Act, 1947:-

(i) S.O.3046(E) published in Gazette of India dated 30th July, 2024, notifying the services, mentioned therein, engaged in the following industrial undertakings to be a public utility service for a further period of six months with effect from 30th July, 2024.

(ii) S.O.3096(E) published in Gazette of India dated 02nd August, 2024, declaring the services mentioned therein engaged in the manufacture of Alumina and Aluminum and mining Bauxite industry to be a public utility service for a further period of six months with effect from the 04th September, 2024.

(iii) S.O.3493(E) published in Gazette of India dated 16th August, 2024, notifying the services mentioned therein engaged in Bank Note Paper Mill India Private limited, Mysore, Karnataka to be a public utility service for a further period of six months with effect from the 19.08.2024.

(iv) S.O.3494(E) published in Gazette of India dated 16th August, 2024, notifying the services mentioned therein, engaged in the industry of transport (Other than railways) for the carriage of passengers or goods, by land or water to be a public utility service for a further period of six months with effect from the 16th August, 2024.

(v) S.O.3495(E) published in Gazette of India dated 16th August, 2024, notifying the services engaged in the Iron and Steel industries to be a public utility service for a further period of six months with effect from the 17th August, 2024.

(vi) S.O.3646(E) published in Gazette of India dated 28th August, 2024, notifying the services engaged in manufacture or production of mineral oil (crude oil), motor and aviation spirit, diesel oil, kerosene oil, fuel oil, diverse hydrocarbon oils and their blends including synthetic fuels, lubricating oils and the like to be a public utility service for further period of six months w.e.f. 28th August, 2024.

(vii) S.O.4486(E) published in Gazette of India dated 14th October, 2024, notifying the services engaged in the Iron Ore Mining to be a public utility service, for a further period of six months w.e.f. 14th October, 2024.

(viii) S.O.4822(E) published in Gazette of India dated 6th November, 2024, notifying the services of the industry engaged in the Lead and Zinc Mining Industry to be a public utility service, for a further period of six months w.e.f. 14th October, 2024.

(ix) S.O.4823(E) published in Gazette of India dated 6th November, 2024, notifying the services engaged in the Bhartiya Reserve Bank Note Mudran (P) Limited, Mysore (Karnataka) and Salboni (West Bengal) to be a public utility service for a period of six months from the date of publication of this notification.

(x) S.O.4828(E) published in Gazette of India dated 6th November, 2024, notifying to declare the services engaged in the Copper Mining industry to be a public utility service for a period of six months w.e.f 7th November, 2024.

(2) A copy of the Employees' Deposit-Linked Insurance (Second Amendment) Scheme, 2024 (Hindi and English versions) published in Notification No. G.S.R. 715(E) in Gazette of India dated 19th November,

2024 under sub-sections (1) and (2) of Section 7 of the Employees' Provident funds and Miscellaneous, Provisions Act, 1952.

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE; AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS (SHRI KIRTI VARDHAN SINGH): Madam, I beg to lay on the Table:-

(1) A copy each of the following Notifications (Hindi and English versions) under Section 26 of the Environment (Protection) Act, 1986:-

(i) The Environment (Protection) Second Amendment Rules, 2024 published in Notification No. S.O. 3864(E) in Gazette of India dated 10th September, 2024.

(ii) The Environment Protection (Manner of Holding Inquiry and Imposition of Penalty) Rules, 2024 published in Notification No. S.O. 4790(E) in Gazette of India dated 4th November, 2024.

(iii) The Environment (Protection) Amendment Rules 2012, published in Notification No. G.S.R. 513(E) in Gazette of India dated 28th June, 2012.

(iv) The Environment (Protection) Amendment Rules, 2017 published in Notification No. S.O. 2537(E) in Gazette of India dated 9th August, 2017.

(v) The Environment (Protection) Second Amendment Rules, 2020 published in Notification No. S.O. 3235(E) in Gazette of India dated 22nd September, 2020.

(vi) The Environment (Protection) Amendment Rules, 2020 published in Notification No. S.O. 1127(E) in Gazette of India dated 18th March, 2020.

(vii) The Environment (Protection) Third Amendment Rules, 2020 published in Notification No. S.O. 4367(E) in Gazette of India dated 3rd December, 2020.

(viii) The Environment (Protection) Amendment Rules, 2021 published in Notification No. S.O. 2346(E) in Gazette of India dated 16th June, 2021.

(ix) The Environment (Protection) Fifth Amendment Rules, 2021 published in Notification No. S.O. 5487(E) in Gazette of India dated 31st December, 2021.

(2) A copy each of the following Notifications (Hindi and English versions) issued under Section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986:-

(i) S.O. 1567(E) published in Gazette of India dated 15th May, 2017, declaring Eco Sensitive Zone around Great Indian Bustard National Park, Rollapadu Wildlife Sanctuary, Andhra Pradesh.

(ii) S.O. 2409(E) published in Gazette of India dated 18th June, 2021, declaring Eco Sensitive Zone around Sri Venkateshwara National Park and Sanctuary, Andhra Pradesh.

(iii) S.O. 2936(E) published in Gazette of India dated 28th August, 2020, declaring Eco Sensitive Zone around Sri Penusila Wildlife Sanctuary, Andhra Pradesh.

(iv) S.O. 3922(E) published in Gazette of India dated 22nd September, 2021, declaring Eco Sensitive Zone around Nagoarjuna Sagar Srisailam Tiger Reserve and Wildlife Sanctuary, Andhra Pradesh.

(v) S.O. 4373(E) published in Gazette of India dated 21st October, 2021, declaring Eco Sensitive Zone around Nagarajunasagar Srisailam Tiger Reserve and Wildlife Sanctuary.

(vi) S.O. 1193(E) published in Gazette of India dated 12th March, 2021, declaring Eco Sensitive Zone around Campbell Bay National Park, Andaman & Nicobar Islands.

(vii) S.O. 1194(E) published in Gazette of India dated 12th March, 2021, declaring Eco Sensitive Zone around Galathea Bay National Park, Andaman & Nicobar Islands.

(viii) S.O. 2020(E) published in Gazette of India dated 29th April, 2022, declaring Eco Sensitive Zone around Mahatma Gandhi Marine National Park, Andaman & Nicobar Islands.

(ix) S.O. 1923(E) published in Gazette of India dated 6th May, 2024, declaring Eco Sensitive Zone around Sessa Orchid Sanctury Eagle Nest WLS & Pakke Tiger Reserve, Arunanchal Pradesh.

(x) S.O. 1718(E) published in Gazette of India dated 30th April, 2021, declaring Eco Sensitive Zone around Kane Wildlife Sanctuary, Arunanchal Pradesh.

(xi) S.O. 3243(E) published in Gazette of India dated 9th August, 2024, declaring Eco Sensitive Zone around Kamlang Wildlife Sanctuary & Namdapha Tiger Reserve, Arunanchal Pradesh.

(xii) S.O. 1716(E) published in Gazette of India dated 30th April, 2021, declaring Eco Sensitive Zone around Chakrashila Wildlife Sanctuary, Assam.

(xiii) S.O. 1923(E) published in Gazette of India dated 25th April, 2022, declaring Eco Sensitive Zone around Panidehing Bird Sanctuary, Assam.

(xiv) S.O. 1924(E) published in Gazette of India dated 25th April, 2022, declaring Eco Sensitive Zone around Barail Wildlife Sanctuary, Assam.

(xv) S.O. 2715(E) published in Gazette of India dated 11th July, 2024, making certain amendments in the Notification No. S.O.1817(E) dated 7th June, 2017.

(xvi) S.O. 70(E) published in Gazette of India dated 10th January, 2017, declaring Eco Sensitive Zone around Bhimbandh Wildlife Sanctuary, Bihar.

(xvii) S.O. 3184(E) published in Gazette of India dated 6th August, 2024, making certain amendments in the Notification No. S.O.71(E) dated 10th January, 2017.

(xviii) S.O. 3736(E) published in Gazette of India dated 2th September, 2024, making certain amendments in the Notification No. S.O.3549(E) dated 2nd September, 2024.

(xix) S.O. 3831(E) published in Gazette of India dated 6th September, 2024, making certain amendments in the Notification No. S.O.70(E) dated 10th January, 2017.

(xx) S.O. 4337(E) published in Gazette of India dated 4th October, 2024, making certain amendments in the Notification No. S.O.3517(E) dated 23rd November, 2016.

(xxi) S.O. 4386(E) published in Gazette of India dated 9th October, 2024, making certain amendments in the Notification No. S.O.2201(E) dated 12th July, 2017.

(xxii) S.O. 834(E) published in Gazette of India dated 22nd February, 2021, making certain amendments in the Notification No. S.O.416(E) dated 20th June, 1991.

(xxiii) S.O. 3592(E) published in Gazette of India dated 2nd September, 2021, making certain amendments in the Notification No. S.O.133(E) dated 4th February, 2003.

(xxiv) S.O. 327(E) published in Gazette of India dated 24th January, 2022, making certain amendments in the Notification No. S.O.884(E) dated 19th December, 1996.

(xxv) S.O. 2820(E) published in Gazette of India dated 21st June, 2022, making certain amendments in the Notification No. S.O.52(E) dated 17th January, 2001.

(xxvi) S.O. 625(E) published in Gazette of India dated 9th February, 2023, making certain amendments in the Notification No. S.O.884(E) dated 19th December, 1996, Maharashtra.

(xxvii) S.O. 1125(E) published in Gazette of India dated 10th March, 2023, making certain amendments in the Notification No. S.O.884(E) dated 19th December, 1996.

(xxviii) S.O. 2133(E) published in Gazette of India dated 9th May, 2023, making certain amendments in the Notification No. S.O.884(E) dated 19th December, 1996.

(xxix) S.O. 4029(E) published in Gazette of India dated 30th September, 2021, amendment 1545(E) dated 25th, June, 2009.

(xxx) S.O. 2994(E) published in Gazette of India dated 12th September, 2017, declaring Eco Sensitive Zone around Neora Valley National Park, West Bengal.

(xxxi) S.O. 3613(E) published in Gazette of India dated 17th November, 2017, declaring Eco Sensitive Zone around Singalila National Park, West Bengal.

(xxxii) S.O. 5836(E) published in Gazette of India dated 26th November, 2018, declaring Eco Sensitive Zone around Raiganj Wildlife Sanctuary, West Bengal.

(xxxiii) S.O. 319(E) published in Gazette of India dated 15th January, 2019, declaring Eco Sensitive Zone around Senchal Wildlife Sanctuary, West Bengal.

(xxxiv) S.O. 1931(E) published in Gazette of India dated 7th June, 2019, declaring Eco Sensitive Zone around Chapramari Wildlife Sanctuary, West Bengal.

(xxxv) S.O. 3151(E) published in Gazette of India dated 30th August, 2019, declaring Eco Sensitive Zone around Ramnabagan Wildlife Sanctuary, West Bengal.

(xxxvi) S.O. 3652(E) published in Gazette of India dated 10th October, 2019, declaring Eco Sensitive Zone around Bibhutibhushan Wildlife Sanctuary, West Bengal.

(xxxvii) S.O. 1962(E) published in Gazette of India dated 18th June, 2020, amendment in the final notification of Eco-sensitive zone around Ramnabagan wildlife Sanctuary.

(xxxviii) S.O. 2937(E) published in Gazette of India dated 28th August, 2020, declaring Eco Sensitive Zone around Ballavpur Wildlife Sanctuary, West Bengal.

(xxxix) S.O. 4500(E) published in Gazette of India dated 14th October, 2024, making certain amendments in the Notification No. S.O.2994(E) dated 11th September, 2017.

(xl) S.O. 2930(E) published in Gazette of India dated 18th December, 2012, declaring Eco Sensitive Area around Bhagirathi, Uttarakhand.

(xli) S.O. 1656(E) published in Gazette of India dated 17th April, 2018, making certain amendments in the Notification No. S.O.2930(E) dated 18th December, 2012.

(xlii) S.O. 94(E) published in Gazette of India dated 6th January, 2020, making certain amendments in the Notification No. S.O.102(E) dated 1st February, 1989.

(xliii) S.O. 5253(E) published in Gazette of India dated 14th November, 2022, making certain amendments in the Notification No. S.O.2930(E) dated 18th December, 2012.

(3) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at Item Nos.[(iii to ix of (1) and Item No. (2)] above.

विधि और न्याय मंत्रालय के राज्य मंत्री; तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल) : महोदया, श्री सुरेश गोपी जी की ओर से, मैं कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा 1(ख) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं :-

(1) (एक) कुमारकृपा फ्रंटियर होटल्स प्राइवेट लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2023-2024 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) कुमारकृपा फ्रंटियर होटल्स प्राइवेट लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2023-2024 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां।

(2) (एक) उत्कल अशोक होटल कारपोरेशन लिमिटेड, कोलकाता के वर्ष 2023-2024 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) उत्कल अशोक होटल कारपोरेशन लिमिटेड, कोलकाता का वर्ष 2023-2024 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां।

(3) (एक) रांची अशोक बिहार होटल कारपोरेशन लिमिटेड, रांची के वर्ष 2023-2024 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) रांची अशोक बिहार होटल कारपोरेशन लिमिटेड, रांची का वर्ष 2023-2024 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां।

(4) (एक) पांडेचेरी अशोक बिहार होटल कारपोरेशन लिमिटेड, पुदुचेरी के वर्ष 2023-2024 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) पांडेचेरी अशोक बिहार होटल कारपोरेशन लिमिटेड, पुदुचेरी का वर्ष 2023-2024 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां।

(5) (एक) इंडिया टूरिज्म डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2023-2024 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा ।

(दो) इंडिया टूरिज्म डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2023-2024 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां।

(6) (एक) पंजाब अशोक होटल कंपनी लिमिटेड, चंडीगढ़ के वर्ष 2023-2024 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा ।

(दो) पंजाब अशोक होटल कंपनी लिमिटेड, चंडीगढ़ का वर्ष 2023-2024 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां।

... (व्यवधान)

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF YOUTH AFFAIRS AND SPORTS (SHRIMATI RAKSHA NIKHIL KHADSE): Madam, I beg to lay on the Table:-

(1) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Sports Authority of India, New Delhi for the year 2023-2024 alongwith audited accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Sports Authority of India, New Delhi, for the year 2023-2024.

(2) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Lakshmibai National Institute of Physical Education, Gwalior, for the year 2022-2023 alongwith audited accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Lakshmibai National Institute of Physical Education, Gwalior, for the year 2022-2023.

(3) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (2) above.

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF EDUCATION; AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF DEVELOPMENT OF NORTH EASTERN REGION (SHRI SUKANTA MAJUMDAR): Madam, I beg to lay on the Table:-

(1) A copy each of the following Notifications (Hindi and English versions) issued under Section 50 of the Indian Institute of Information Technology Act, 2014:-

(i) The Indian Institute of Information Technology, Allahabad (Amendment) Statutes, 2024 published in Notification No. S.O. 3230(E) in Gazette of India dated 9th August, 2024.

(ii) The Indian Institute of Information Technology, Design and Manufacturing, Kurnool (Amendment) Statutes, 2024 published in Notification No. S.O. 3226(E) in Gazette of India dated 9th August, 2024.

(iii) The Indian Institute of Information Technology, Design and Manufacturing, Kancheepuram (Amendment) Statutes, 2024 published in Notification No. S.O. 3227(E) in Gazette of India dated 9th August, 2024.

(iv) The Pt. Dwarka Prasad Mishra – Indian Institute of Information Technology, Design and Manufacturing, Jabalpur (Amendment) Statutes, 2024 published in Notification No. S.O. 3228(E) in Gazette of India dated 9th August, 2024.

(v) The Atal Bihari Vajpayee – Indian Institute of Information Technology and Management, Gwalior (Amendment) Statutes, 2024 published in Notification No. S.O. 3229(E) in Gazette of India dated 9th August, 2024.

(2) A copy of the Council of Architecture (Amendment) Rules, 2024 (Hindi and English versions) published in Notification No. G.S.R.512(E) in Gazette of India dated 20th August, 2024 under sub-section (3) Section 45 of the Architects Act, 1972

(3) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Indian Institute of Technology, Madras, Chennai, for the year 2023-2024.

(ii) A copy of the Annual Accounts (Hindi and English versions) of the Indian Institute of Technology, Madras, Chennai, for the year 2023-2024 together with audit report thereon.

(iii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Indian Institute of Technology, Madras, Chennai, for the year 2023-2024.

(4) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Indian Institute of Management, Bangalore, for the year 2023-2024 alongwith audited accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Indian Institute of Management, Bangalore, for the year 2023-2024.

(5) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Indian Institute of Management, Udaipur, for the year 2023-2024 alongwith audited accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Indian Institute of Management, Udaipur, for the year 2023-2024.

(6) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Indian Institute of Technology, Visakhapatnam, for the year 2023-2024 alongwith audited accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Indian Institute of Technology, Visakhapatnam, for the year 2023-2024.

(7) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the National Institute of Technology, Patna, for the year 2023-2024 alongwith audited accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the National Institute of Technology, Patna, for the year 2023-2024.

(8) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the National Institute of Technology, Sikkim, for the year 2023-2024 alongwith audited accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the National Institute of Technology, Sikkim, for the year 2023-2024.

(9) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the National Institute of Technology Uttarakhand, Pauri Garwal, for the year 2023-2024 alongwith audited accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the National Institute of Technology Uttarakhand, Pauri Garwal, for the year 2023-2024.

(10) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Indian Institute of Technology, Jodhpur, for the year 2023-2024.

(ii) A copy of the Annual Accounts (Hindi and English versions) of the Indian Institute of Technology, Jodhpur, for the year 2023-2024, together with audit report thereon.

(iii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Indian Institute of Technology, Jodhpur, for the year 2023-2024.

(11) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Indian Institute of Technology, Delhi, for the year 2023-2024.

(ii) A copy of the Annual Accounts (Hindi and English versions) of the Indian Institute of Technology, Delhi, for the year 2023-2024, together with audit report thereon.

(iii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Indian Institute of Technology, Delhi, for the year 2023-2024.

(12) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Indian Institute of Technology (Indian School of Mines), Dhanbad, for the year 2023-2024 alongwith audited accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Indian Institute of Technology (Indian School of Mines), Dhanbad, for the year 2023-2024.

(13) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Indian Institute of Science Education and Research, Mohali, for the year 2023-2024

(ii) A copy of the Annual Accounts (Hindi and English versions) of the Indian Institute of Science Education and Research, Mohali, for the year 2023-2024, together with audit report thereon.

(iii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Indian Institute of Science Education and Research, Mohali, for the year 2023-2024.

(14) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Association of Indian Universities, New Delhi, for the year 2023-2024, alongwith audited accounts

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Association of Indian Universities, Indian, for the year 2023-2024.

(15) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Indian Council of Philosophical Research, New Delhi, for the year 2022-2023.

(ii) A copy of the Annual Statement of Accounts (Hindi and English versions) of the Indian Council of Philosophical Research, New Delhi, for the year 2022-2023.

(iii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Indian Council of Philosophical Research, New Delhi, for the year 2022-2023.

(16) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (15) above.

(17) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Indian Institute of Technology, Allahabad, for the year 2023-2024.

(ii) A copy of the Annual Accounts (Hindi and English versions) of the Indian Institute of Technology, Allahabad, for the year 2023-2024, together with audit report thereon.

(iii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Indian Institute of Technology, Allahabad, for the year 2023-2024.

(18) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Indian Institute of Technology, Kottayam, for the year 2023-2024 alongwith audited accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Indian Institute of Technology, Kottayam, for the year 2023-2024.

(19) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Indian Institute of Information Technology, Raichur, for the year 2023-2024.

(ii) A copy of the Annual Accounts (Hindi and English versions) of the Institute of Information Technology, Raichur, for the year 2023-2024, together with audit report thereon.

(iii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Institute of Information Technology, Raichur, for the year 2023-2024.

(20) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Indian Institute of Information Technology, Bhagalpur, for the year 2023-2024.

(ii) A copy of the Annual Accounts (Hindi and English versions) of the Institute of Information Technology, Bhagalpur, for the year 2023-2024, together with audit report

(iii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Institute of Information Technology, Bhagalpur, for the year 2023-2024.

(21) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Avinashilingam Institute for Home Science and Higher Education for Women, Coimbatore, for the year 2022-2023.

(ii) A copy of the Annual Accounts (Hindi and English versions) of the Avinashilingam Institute for Home Science and Higher Education for Women, Coimbatore, Tamil Nadu, for the year 2022-2023, together with audit report thereon.

(iii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Avinashilingam Institute for Home Science and Higher Education for Women, Coimbatore, Tamil Nadu, for the year 2022-2023.

(22) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (21) above.

(23) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Indian Institute of Information Technology Design and Manufacturing, Kurnool, Kurnool, for the year 2023-2024.

(ii) A copy of the Annual Accounts (Hindi and English versions) of the Indian Institute of Information Technology Design and Manufacturing, Kurnool, Kurnool, for the year 2023-2024, together with audit report thereon.

(iii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Indian Institute of Information Technology Design and Manufacturing, Kurnool, Kurnool, for the year 2023-2024.

(24) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Avinashilingam Institute for Home Science and Higher Education for Women, Coimbatore, for the year 2023-2024.

(ii) A copy of the Annual Accounts (Hindi and English versions) of the Avinashilingam Institute for Home Science and Higher Education for Women, Coimbatore, for the year 2023-2024, together with audit report thereon.

(iii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Avinashilingam Institute for Home Science and Higher Education for Women, Coimbatore, Tamil Nadu, for the year 2023-2024.

(25) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Indian Institute of Information Technology, Design and Manufacturing, Kancheepuram, for the year 2023-2024.

(ii) A copy of the Annual Accounts (Hindi and English versions) of the Indian Institute of Information Technology, Design and Manufacturing, Kancheepuram, for the year 2023-2024, together with audit report thereon.

(iii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Indian Institute of Information Technology, Design and Manufacturing, Kancheepuram, for the year 2023-2024.

(26) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Pondicherry University, Puducherry, for the year 2022-2023.

(ii) A copy of the Annual Accounts (Hindi and English versions) of the Pondicherry University, Puducherry, for the year 2022-2023, together with audit report thereon.

(iii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Pondicherry University, Puducherry, for the year 2022-2023.

(27) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (26) above.

(28) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Indian Institute of Management, Mumbai for the year 2023-2024.

(ii) A copy of the Annual Accounts (Hindi and English versions) of the Indian Institute of Management, Mumbai, for the year 2023-2024, together with audit report thereon.

(iii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Indian Institute of Management, Mumbai, for the year 2023-2024.

(29) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Indian Institute of Information Technology, Dharwad, for the year 2023-2024, alongwith audited accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Indian Institute of Information Technology, Dharwad, for the year 2023-2024.

(30) (i) A copy each of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Mahatma Gandhi Central University, Motihari, for the years 2020-2021 and 2021-2022.

(ii) A copy each of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Mahatma Gandhi

Central University, Motihari, for the years 2020-2021 and 2021-2022.

(31) Two Statements (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (30) above.

(32) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Indian Institute of Information Technology, Nagpur, for the year 2023-2024, alongwith audited accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Indian Institute of Information Technology, Nagpur, for the year 2023-2024.

(33) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Indian Institute of Information Technology, Kota, for the year 2023-2024, alongwith audited accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Indian Institute of Information Technology, Kota, for the year 2023-2024.

कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हर्ष मल्होत्रा) : महोदया, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 469 की उप-धारा (4) के अंतर्गत जारी निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) कंपनी (शास्तियों का न्यायनिर्णयन) संशोधन नियम, 2024 जो दिनांक 5 अगस्त, 2024 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 476(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) कंपनी (विदेशी कंपनियों का रजिस्ट्रीकरण) संशोधन नियम, 2024 जो दिनांक 12 अगस्त, 2024 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 491(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) कंपनी (भारतीय लेखांकन मानक) संशोधन नियम, 2024 जो दिनांक 12 अगस्त, 2024 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 492(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(चार) कंपनी (समझौते, ठहराव और समामेलन) संशोधन नियम, 2024 जो दिनांक 9 सितम्बर, 2024 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 555(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(पांच) कंपनी (भारतीय लेखांकन मानक) दूसरा संशोधन नियम, 2024 जो दिनांक 9 सितम्बर, 2024 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 554(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(छह) कंपनी (प्रोस्पेक्टस और प्रतिभूतियों का आवंटन) संशोधन नियम, 2024 जो दिनांक 20 सितम्बर, 2024 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 583(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(सात) कंपनी (लेखा) संशोधन नियम, 2024 जो दिनांक 24 सितम्बर, 2024 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 587(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(आठ) कंपनी (भारतीय लेखांकन मानक) तीसरा संशोधन नियम, 2024 जो दिनांक 28 सितम्बर, 2024 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 602(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(नौ) कंपनी (शास्तियों का न्यायनिर्णयन) दूसरा संशोधन नियम, 2024 जो दिनांक 9 अक्तूबर, 2024 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 630(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(2) सीमित दायित्व भागीदारी अधिनियम, 2008 की धारा 79 की उप-धारा (3) के अंतर्गत सीमित दायित्व भागीदारी (संशोधन) नियम, 2024 जो दिनांक 5 अगस्त, 2024 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 475(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) (एक) भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग, नई दिल्ली के वर्ष 2023-2024 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग, नई दिल्ली के वर्ष 2023-2024 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

... (व्यवधान)

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति

विवरण

डॉ. फग्गन सिंह कुलस्ते (मंडला) : महोदया, मैं अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति (2024-25) के निम्नलिखित विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) ''सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण तथा अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए पेट्रोल और गैस एजेंसियों (सीएनजी, पीएनजी, एलपीजी आदि) और अन्य संबंधित एजेंसियों, इकाईयों के आवंटन की स्थिति'' विषय के बारे में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति के 28वें प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा) के अध्याय-एक में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार का अंतिम-की-गई-कार्रवाई संबंधी विवरण।

(2) ''राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम (एनएसएफडीसी) के कार्यकरण की समीक्षा'' विषय के बारे में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति के 29वें प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा) के अध्याय-एक में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार का अंतिम-की-गई-कार्रवाई संबंधी विवरण।

… (व्यवधान)

STANDING COMMITTEE ON RURAL DEVELOPMENT AND PANCHAYATI RAJ

Statement

SHRI SAPTAGIRI SANKAR ULAKA (KORAPUT): Madam, I beg to lay on the Table a Statement (Hindi and English versions) of the Standing Committee on Rural Development and Panchayati Raj on the Thirty-sixth Report (Seventeenth Lok Sabha) on Action Taken by the Government on the recommendations contained in Thirty-second Report (Seventeenth Lok Sabha) on “Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana - (PMGSY)” (2022-23) of the Ministry of Rural Development (Department of Rural Development)'.

माननीय सभापति: माननीय श्री तनुज पुनिया जी, माननीय मणिक्कम टैगोर जी, माननीय सुश्री जोतिमणि जी, माननीय सुश्री प्रणिती शिंदे जी, माननीय श्री गौरव गोगोई जी, माननीय सुश्री शैलजा जी, आप सभी के नोटिसेज प्राप्त हुए हैं और विचाराधीन हैं।

… (व्यवधान)

माननीय सभापति: मैं माननीय सभी सदस्यों से आग्रह कर रही हूं कि सभी माननीय सदस्यों के शून्य काल में बड़े महत्वपूर्ण विषय हैं।

… (व्यवधान)

माननीय सभापति : माननीय सदस्य, श्री देवेश शाक्य जी।

… (व्यवधान)

श्री धर्मेन्द्र यादव (आज़मगढ़) : सभापति जी, पूरे देश के किसान परेशान हैं।… (व्यवधान)

माननीय सभापति: माननीय सदस्य श्री देवेश शाक्य जी, क्या आप बोलना नहीं चाहते हैं?

… (व्यवधान)

(1205/CP/SAN)

माननीय सभापति (श्रीमती संध्या राय) : देवेश शाक्य जी, आप बोलिए।

… (व्यवधान)

माननीय सभापति : सभा की कार्यवाही दो बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

… (व्यवधान)

1205 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा चौदह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

(1400/NK/SNT)

लोक सभा चौदह बजे पुनः समवेत् हुई।

(श्रीमती संध्या राय पीठासीन हुईं)

…(व्यवधान)

1400 hours

(At this stage, Shri B. Manickam Tagore and some other hon. Members came and stood near the Table)

नियम 377 के अधीन मामले – सभा पटल पर रखे गए

1400 बजे

माननीय सभापति : जिन माननीय सदस्यों को आज नियम 377 के अधीन मामलों को उठाने की अनुमति प्रदान की गई है, वे अपने मामले के अनुमोदित पाठ को तुरंत व्यक्तिगत रूप से सभा पटल पर रख दें।

Re: Need to develop a special policy for disposal of Enemy Properties

SHRI PARSHOTTAMBHAI RUPALA (RAJKOT): It is evident that enemy properties are not being managed properly, due to which many obstacles are arising in the auction process. Auctioning of these properties can be significant from the financial point of view and also opportunity for the Central Government to make revenue out of it. I urge the Central Government to develop a special policy for speedy disposal of enemy Properties. (ends)

Re: Need to set up a Handloom Park in Jogulamba Gadwal district, Telangana

SHRIMATI D. K. ARUNA (MAHBUBNAGAR): I would like to bring to your kind notice the dire need to set up a Handloom Park in Jogulamba Gadwal District which falls in erstwhile Mahabubnagar District in Telangana State, which is a long-pending demand. Jogulamba Gadwal is known for its handloom Jari chiralu (Gadwala sarees) in rural and semi-rural areas of our country like Jogutamba Gadwal, the handloom industry is a significant source of livelihood and a representation of the diverse and rich cultural history of our nation since many decades. With more than 70 per cent of all weavers and associated workers being women, it is also a sector that specifically addresses the empowerment of women and boosts export revenue of our country. For this purpose, 50 acres of land was allotted ten years ago, but no progress was made. There are about 18000 to 20000 families who are directly or indirectly dependent on Handloom related works for their livelihood in Jogulamba Gadwal. They are in distress and leading a pathetic life and to address these issues. They need financial assistance from the Government under various schemes like National Handloom Development Programme, Comprehensive Handloom Cluster Development Scheme, Handloom Weavers Comprehensive Welfare Scheme, Weavers Mudra Scheme and Yarn Supply Scheme. Therefore, I request Hon'ble Minister of Textiles to kindly consider to set up a Handloom Park in Jogulamba Gadwal District. (ends)

Re: Need to establish a heliport in Kapilvastu in Siddharthnagar district, Uttar Pradesh under UDAN Scheme

श्री जगदम्बिका पाल (डुमरियागंज) : कपिलवस्तु, जिला सिद्धार्थनगर, उत्तर प्रदेश, भगवान बुद्ध की जन्मस्थली, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक रूप से महत्वपूर्ण है और बौद्ध धर्म के अनुयायियों के लिए आस्था का केंद्र है। यह बौद्ध परिपथ के प्रमुख स्थलों में से एक है, जिसमें कुशीनगर, बोधगया, सारनाथ, और श्रावस्ती जैसे स्थान शामिल हैं। सरकार की उड़ान (UDAN) योजना ने इन स्थलों को हवाई संपर्क से जोड़कर यात्रियों के लिए सुविधा बढ़ाई है।दुर्भाग्यवश, कपिलवस्तु को अभी तक इस योजना के तहत हवाई कनेक्टिविटी या हेलीपोर्ट की सुविधा नहीं मिली है। इससे पर्यटन की संभावनाओं और वैश्विक बौद्ध अनुयायियों की सुविधा प्रभावित हो रही है। कपिलवस्तु में हेलीपोर्ट की स्थापना न केवल कनेक्टिविटी में सुधार करेगी, बल्कि स्थानीय विकास, रोजगार और पर्यटन को भी बढ़ावा देगी।मैं सरकार से निवेदन करता हूं कि उड़ान योजना के तहत कपिलवस्तु में हेलीपोर्ट की स्थापना को प्राथमिकता दी जाए, जिससे यह स्थल बौद्ध परिपथ के अन्य स्थलों के बराबर सम्मान और सुविधाएं प्राप्त कर सके। (इति)

Re: Need to enforce the directives of National Green Tribunal and Supreme Court against illegal construction in Himachal Pradesh and Uttarakhand

SHRI RAJIV PRATAP RUDY (SARAN): I rise to highlight the catastrophic impact of human-induced activities, including illegal construction, on the fragile ecosystems of Himachal Pradesh and Uttarakhand. Unregulated road expansion, and unauthorized buildings have triggered landslides, destabilized mountains, and caused irreparable damage to these ecologically sensitive zones. The tragic subsidence in Joshimath and similar incidents underscore the consequences of ignoring scientific warnings and violating environmental norms. The Supreme Court and National Green Tribunal (NGT) have repeatedly emphasized the need for adherence to environmental guidelines, recommending strict enforcement of construction regulations and declaring vulnerable regions as "no-construction zones." Despite multiple committee reports highlighting the role of unscientific activities in exacerbating disasters, implementation remains weak. I urge the Government to enforce all NGT and Supreme Court directives, ensure strict action against illegal construction, and mandate comprehensive environmental impact assessments for all projects. (ends)

Re: Need to promote Jalpaiguri in West Bengal as a heritage tourism destination

DR. JAYANTA KUMAR ROY (JALPAIGURI): I wish to draw the attention of this august House to the rich spiritual and cultural heritage of Jalpaiguri, West Bengal. The Jalpesh Temple, built in the traditional Kamrup style and dedicated to Lord Shiva, dates back to the 9th century and is especially revered during the Jalpaiguri monsoon festival. The Bhramridevi Temple along with the Garteshwari Temple forms part of the revered Shaktipeeth, is a prominent spiritual site surrounded by natural beauty, attracting devotees year-round. The Jotileshwar Temple, another ancient Shiva temple, has deep historical and mythological roots tied to the region's rulers. The Devi Choudhurani Temple, linked to the legendary revolutionary Devi Choudhurani and her accomplices Darpadeb Raikat and Bhabani Pathak, embodies the area’s rich history of resistance against British rule. These temples, scattered across the district, can form a vibrant "Heritage and Pilgrimage Tourism Circuit", promoting spiritual tourism. Development of this circuit with improved roads, visitor amenities, and promotional efforts would attract pilgrims and tourists, create employment, and preserve the region's cultural legacy. I urge the Ministry of Tourism to consider this proposal under relevant schemes to promote Jalpaiguri as a heritage tourism destination. (ends)

Re: Need for a bypass road for Junagarh NAC in Kalahandi Parliamentary Constituency

SHRIMATI MALVIKA DEVI (KALAHANDI): I would like to request our Honourable Minister of Road Transport and Highways for a bypass at Junagarh town because the national highway is crossing the town due to which big trucks, dumper and other large vehicles make this road crowded thereby causing traffic jams accidents and inconvenience to the people of Junagarh town. Many mishaps have happened in the past and hence, I would earnestly request for a bypass road for Junagarh NAC area. It is a big town which is hugely populated and five other blocks, viz. Koksara, Dharamgarh, Jaiptana, Golamunda, Kalampur and Thuamaulrampur have to cross the town to reach the headquarters of Bhawanipatna. Hence it is a big need as it is the central point of major traffic and only a bypass road can lead to make the lives of everyone easier. Hence, I request that this demand of people of my Parliamentary Constituency will be looked into and executed as soon as possible.

(ends)

Re: Need to develop a centralized system for conversion and utilization of agriculture waste to garner optimum results in agriculture and animal husbandry sectors

श्री रोडमल नागर (राजगढ़) : सरकार ने प्राकृतिक कृषि की ओर तेजी से कदम बढ़ाए हैं। कृषि से उत्पन्न अपशिष्ट का प्रयोग यदि पशुपालन मे किया जाता है तो कृषि का वेस्ट पशुओं के लिए बैस्ट बन जाता है और यदि पशुओं द्वारा उत्सर्जित वेस्ट का उपयोग जब कृषि हेतु किया जाता है तो यह कृषि के लिए बैस्ट बन जाता है। जब देसी गायों के द्वारा कृषि उत्सर्जित वेस्ट का प्रयोग आहार के रूप में किया जाता है तो यह स्वास्थ्य वर्धक एवं बहु उपयोगी A-2 दूध के उत्पादन एवं गुणवत्ता दोनों में वृद्धि करता है। कृषि से प्राप्त वेस्ट से अच्छी नस्ल की देसी गाय तैयार होती है। अतः सरकार से प्राकृतिक कृषि ,पशुपालन ,नस्लसुधार, दुग्ध एवं खाद्यान्न उत्पादकता के साथ ही गुणवत्ता में वृद्धि करने हेतु waste से best बनाकर बहुआयामी एवं बहुपयोगी एकीकृत तंत्र विकसित करने हेतु अनुरोध करता हूं।

(इति)

Re: Need to construct railway over bridge/underpass at railway crossings in Misrikh Parliamentary Constituency

श्री अशोक कुमार रावत (मिश्रिख) : मेरे संसदीय क्षेत्र मिश्रिख के अंतर्गत नगर पालिका बिल्हौर क्रॉसिंग लेवल संख्या- 64, व नगर पंचायत कछौना के अंतर्गत बालामऊ जंक्शन क्रॉसिंग संख्या- 258, चौबेपुर, और शिवराजपुर क्रॉसिंग संख्या 43 से निकलने वाली रेलवे क्रॉसिंग पर भारी यातायात होने के कारण क्रॉसिंग बंद होने पर सड़कों पर वाहनों की लंबी कतार लग जाती है। कई कई घंटे जाम लगा रहता है। लोग घंटो जाम में फंसे रहते हैं। आम लोग ही नहीं प्रशासनिक अधिकारी, आपातकालीन एंबुलेंस भी जाम में फंसे रहते हैं। जिसके चलते मरीजों को अपनी जान भी गंवानी पड़ी है। इससे स्थानीय लोगों को आने-जाने में काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। यहां के लोग काफी समय से रेलवे ओवर ब्रिज या अंडरपास बनाए जाने की मांग कर रहे हैं। ओवर ब्रिज का निर्माण हो जाए तो जाम की समस्या से निजात मिल सकेगी। मैं माननीय रेल मंत्री जी से मांग करता हूं कि बिल्हौर, बालामऊ जंक्शन, चौबेपुर, शिवराजपुर में रेलवे ओवर ब्रिज या अंडरपास का निर्माण करने के लिए आवश्यक कदम उठाया जाय।

(इति)

Re: Need to provide houses under Pradha Mantri Awas Yojana to families presently living in Tin Shed houses

डॉ. भोला सिंह (बुलन्दशहर) : प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) का उद्देश्य देश के हर नागरिक को पक्का घर उपलब्ध कराना है। हालांकि, इस योजना में ऐसे घरों को पात्रता से बाहर रखा गया है जिनकी छतें टीन की बनी हुई हैं। यह निर्णय ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में रहने वाले उन लाखों परिवारों के लिए असुविधाजनक साबित हो रहा है, जिनके घर स्थायी दीवारों के बावजूद टीन की छतों के कारण इस योजना के लाभ से वंचित हो रहे हैं।टीन की छतें मौसम की मार, गर्मी और ठंड से पर्याप्त सुरक्षा प्रदान नहीं करती हैं और न ही ये लंबे समय तक टिकाऊ होती हैं। ऐसे में, इन घरों को पक्का घर बनाने के लिए योजना के तहत पात्रता में शामिल करना आवश्यक है। मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत टीन की छतों वाले घरों को भी योजना का लाभ प्रदान करने हेतु संशोधन किया जाए। इससे योजना के उद्देश्यों को अधिक प्रभावी तरीके से पूरा किया जा सकेगा।

(इति)

Re: Need to restart Lal Imli Mill of Kanpur, Uttar Pradesh

श्री रमेश अवस्थी (कानपुर) : माननीय कपड़ा मंत्री जी आपका ध्यान कानपुर नगर में ब्रिटिश काल से संचालित एवं वर्तमान से पिछले कई वर्षों से बंद पड़ी ऐतिहासिक लाल इमली मिल की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ जो एक समय पर हज़ारों लोगों का रोज़गार का केंद्र हुआ करती थी, लाल इमली को कानपुर की धरोहर के रूप में जाना जाता है, इसके बने वूलेन क्लॉथ की माँग इंग्लैंड अमेरिका रुस और जर्मनी तक थी जिसने कानपुर को देश ही नहीं बल्कि विदेशों तक एक अलग पहचान दिलाई थी। कानपुर की कभी शान होने वाली लाल इमली मिल अब पूरी तरह से बंद है। इसके बंद होने से यहां के कर्मचारियों और उनके परिवारों के समक्ष गंभीर आर्थिक समस्याएं उत्पन्न हो गई हैं। कर्मचारियों का पिछले कई वर्षों से लंबित वेतन, ग्रेचुइटी, और अन्य बकाया भुगतान की स्थिति अत्यधिक चिन्ताजनक है। दिनांक 29 अगस्त २०२४ को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने कानपुर में लाल इमली मिल को पुनः चालू कराने की घोषणा भी की थी।
मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि आप इस मुद्दे को शीघ्र संज्ञान में लें और लाल इमली मिल को पुनः चालू करने एवं कर्मचारियों का लंबित वेतन, ग्रेचुइटी और अन्य बकाया भुगतान की दिशा में आवश्यक कदम उठाएं। (इति)

Re: Need to take comprehensive measures to protect the river Periyar in Kerala from industrial pollution

SHRI HIBI EDEN (ERNAKULAM): I wish to draw the attention of this House to the issue of mass fish mortality events in Kerala that have brought untold suffering to the local communities and raised alarming concerns about environmental degradation. The Periyar River, which is the lifeline for approximately 5.5 million residents of central Kerala, has seen frequent fish killing incidents in the recent past that has led to substantial ecological, economic and social impact. One such devastating incident occurred in May 2024 which resulted in the loss of fish stocks worth over Rs. 41 Crores. Studies have confirmed that these fish kills are directly linked to industrial pollution. A fundamental issue underlying such pollution is the failure of the Kerala State Pollution Control Board (KSPCB) to carry out its duties. I urge this House to consider for establishment of a Permanent Surveillance Centre, provide compensation to affected Fishers and Farmers, initiation for comprehensive river ecology restoration and strengthen Pollution Control Mechanism. I, accordingly, call upon the Hon'ble Minister to take swift action to protect the Periyar river from further degradation. (ends)

Re: Rehabilitation of people living on railway land in Mumbai

प्रो. वर्षा एकनाथ गायकवाड़ (मुम्बई उत्तर-मध्य) : मुंबई जैसे महानगर में 50% से अधिक लोग झुग्गियों में अस्वस्थ और असुरक्षित परिस्थितियों में रहने को मजबूर हैं। ये झुग्गियां निजी, राज्य सरकार, नगर निगम, केंद्र सरकार, रेलवे और हाउसिंग बोर्ड की जमीनों पर स्थित हैं। महाराष्ट्र सरकार ने 1971 के स्लम सुधार अधिनियम के तहत झुग्गियों के पुनर्विकास और पुनर्वास की योजना बनाई थी, जिसमें यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि झुग्गियों को हटाने की स्थिति में उनका उचित पुनर्वास सुनिश्चित किया जाए। हालांकि, रेलवे परिसरों पर स्थित झुग्गियों के अतिक्रमण के मामले में रेलवे प्रशासन ने नोटिस जारी किए हैं,लेकिन इन झुग्गियों के पुनर्वास का कार्य केंद्र और राज्य सरकार के समन्वय के अभाव में रुका हुआ है। इस पुनर्वास प्रक्रिया में एमएमआरडीए, सिडको, म्हाडा और मुंबई नगर निगम की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है।केंद्र सरकार से 'No Objection Certificate' प्राप्त करना भी इस प्रक्रिया की प्राथमिक आवश्यकता है। केंद्र और महाराष्ट्र सरकार से आग्रह है कि मिलकर एक सुनियोजित नीति तैयार करें और रेलवे परिसरों के आसपास रहने वाले लोगों के पुनर्वास कार्य को शीघ्र लागू करें। यह न केवल इन परिवारों को सुरक्षित और गरिमापूर्ण जीवन देगा।

(इति)

Re: Need to curb incidents of cyber fraud

श्री बलवंत बसवंत वानखडे (अमरावती) : धोखाधड़ी करने वाले आम तौर पर लोगों को कॉल, फोन संदेश, ईमेल और व्हाट्सएप लिंक के माध्यम से जोड़ते हैं और उन्हें अपनी व्यक्तिगत जानकारी साझा करने के लिए मनाने की कोशिश करते हैं। ये बैंक खाते का विवरण, लॉगिन आईडी और पासवर्ड हो सकते हैं, या पीड़ित को उनके साझा लिंक के साथ एक एप्लिकेशन इंस्टॉल करने के लिए कह सकते हैं। कभी-कभी, वे डर पैदा करने की तकनीक का इस्तेमाल करते हैं,

आम लोग ऑनलाइन फ्रॉड की आशंका से चिंताग्रस्त रहते हैं। अधिकतर लोग डिजिटल गिरफ्तारी के तरीके से अनजान हैं। मेरा सरकार से अनुरोध है कि ऑनलाइन धोखाधड़ी के मामलों पर रोक लगाने हेतु तुरंत आवश्यक कदम उठाए जाएं।

(इति)

Re: Need to grant adequate funds for upgradation of the ESIC Hospital in Tirunelveli, Tamil Nadu

SHRI ROBERT BRUCE C. (TIRUNELVELI): Tirunelveli is home to an ESI Hospital which is presently a 100 bedded unit. The hospital is primarily used by Government employees and faces a host of issues which have to be rectified to provide quality healthcare to the people of Tirunelveli. There are multiple vacancies for the posts of Doctors and Nurses which have to be filled up effectively for the hospital to function around the clock, seamlessly. The hospital should also be upgraded to a 300 bedded hospital with advanced medical equipment such as Digital X-ray Machines, CT Scan Machines, MRI Machines, Critical Care Unit, Cath Lab and Oncology unit so as to benefit the people of Tirunelveli. The Union Government should take cognizance of the same and must immediately pass necessary orders and sanction adequate funds for the upgradation of the ESIC Hospital, Tirunelveli.

(ends)

Re: Need to address the problems of flood and erosion caused by river Brahmaputra in Assam

MD. RAKIBUL HUSSAIN (DHUBRI): Due to river erosion, Assam loses approximately 8,000 hectares of fertile land annually. In the past 50 years, nearly 4,000 square kilometres, or 7.4% of the State's area, has been lost. The floods worsen the situation, affecting over 30% of Assam's population annually. In 2023 alone, 20 districts and over 100,000 people were impacted. Despite its severity since ages, river erosion in Assam was recently recognized as a natural calamity by the 15th Finance Commission. However, bureaucratic inefficiencies often hinder the effective distribution of the funds to beneficiaries. Sir, recurring soil erosion and floods caused by the Brahmaputra and its tributaries in Assam are a national concern. Therefore, I urge the Ministry of Home Affairs (Disaster Management Division) and the Ministry of Jal Shakti to take immediate, coordinated action to mitigate its impact and declare the flood & erosion problem of Assam as a national problem.

(ends)

Re: Stoppage of trains and upgradation of halt stations to full-fledged railway stations in Ballia and Ghazipur districts of Uttar Pradesh

श्री सनातन पांडेय (बलिया) : फेफना रेलवे स्टेशन जिला बलिया एवं यूसुफपुर रेलवे स्टेशन, जिला गाजीपुर, उत्तर प्रदेश में कोविड पूर्व काल में एक्सप्रेस ट्रेनों का ठहराव था, जो कि कोविड काल में बंद कर दिया गया। मेरा सरकार से निवेदन है कि एक्सप्रेस ट्रेनों का ठहराव उपरोक्त स्टेशनों पर पूर्व की भांति किया जाए।

कोविड काल में पूर्व में रेवती रेलवे स्टेशन, जिला बलिया एवं ताजपुर स्टेशन जिला गाजीपुर को कोविड काल के दौरान हाल्ट स्टेशन में परिवर्तित कर दिया गया था जिससे यात्रियों का भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मेरा सरकार से अनुरोध है कि उपरोक्त दोनों स्टेशनों को हाल्ट स्टेशन के बजाय पूर्ण रूप से रेलवे स्टेशन का दर्जा दिया जाए।

(इति)

Re: Action taken in the incident of boiler blast at NTPC Plant in Unchahar, Raibareli, Uttar Pradesh

श्री आदित्य यादव (बदायूं) : 1 नवंबर 2017 को ऊंचाहार रायबरेली में एनटीपीसी ब्वॉयलर विस्फोट में की गई जांच में कुल कितने लोगों को दोषी पाया गया।

दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई कृपया जांच रिपोर्ट तथा दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध की गई कार्रवाई भी उपलब्ध करने का कष्ट करें।

क्या सरकार की जानकारी में है इस घटना में मुख्य रूप से दोषी पाए गए एक व्यक्ति को सेवा समाप्ति कर एनटीपीसी के ज्वाइंट वेंचर कंपनी EESL में 2 माह के बाद उन्हें नौकरी पर रख दिया जहां से वह सकुशल अवकाश प्राप्त हो गए?

क्या सरकार इसकी जांच कर दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कार्रवाई करेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं तो क्यों?

(इति)

Re: Need to adhere to robust pharmaceutical regulatory framework to ensure transparency in pharmaceuticals distribution and procurement process

SHRI KIRTI AZAD (BARDHAMAN-DURGAPUR): The Drugs Consultative Committee has recently made the Good Distribution Practices (GDP) guidelines for pharmaceuticals non-mandatory, despite recommending their mandatory implementation in its 54th meeting in 2018. These guidelines are essential for maintaining the quality and integrity of pharmaceutical products throughout the distribution process, covering processes but not limited to procurement, purchasing, and storage. By making these guidelines non-mandatory, we lose the ability to penalize non-compliance, thereby weakening our pharmaceutical regulatory framework. This decision is particularly alarming given the findings of the National Drug Survey (2014-16), which reported that Not of Standard Quality (NSQ) drugs are three times more prevalent in Government procurement than in retail. The West Bengal Government's strict adherence to its State Inventory Control Guidelines has successfully kept out-of-pocket expenditure low while ensuring transparency in procurement process—a model the nation should emulate. The ongoing issue of spurious and substandard drugs highlights the urgent need for robust regulatory measures to protect public health. I urge the CDCSO and Ministry of Health and Family welfare to implement Good Distribution Practices guidelines for pharmaceuticals with legal sanctity to strengthen the pharmaceutical supply chain and safeguard the well-being of our citizens. (ends)

Re: Problems to be faced by sugarcane farmers due to proposed implementation of Sugarcane (Control) Order-2024

SHRI MALAIYARASAN D. (KALLAKURICHI): The Union Government is removing the legal sections that benefited for sugarcane farmers one by one in the currently in force Sugarcane Control Order-1966. They have repealed section 5A, which allowed sugar mills to give additional prices to farmers from the profits they make. They have repealed the legal section in the Sugarcane (Control) Order-1966, which allowed State Governments to announce and provide State Advised Price to protect the interests of sugarcane farmers. The Union Government has now announced about the Sugarcane (Control) Order-2024 and has sought opinions from sugar mills and State Sugar Departments. The Sugar (Control) Order-2024 bill, states that the Union Government must obtain permission to sell sugar and by-products including ethanol produced by sugar mills. The Sugar (Control) Order 2024 Bill states that even if sugar mills are asked to sell sugar pledged in banks. If this law is implemented, the 1966 law, which requires sugar mills to pay sugarcane to farmers within 14 days, will be repealed. Currently, the Union Government is setting monthly targets for the sale of sugar produced by sugar mills. As a result, sugar mills are struggling to sell sugar on time. (ends)

Re: Problems being faced by the employees of Kendriya Vidyalayas in the country

SHRI LAVU SRIKRISHNA DEVARAYALU (NARASARAOPET): I write to draw your attention to the urgent needs of Kendriya Vidyalaya (KV) employees, who have dedicated their lives to educating the children of our nation. Firstly, KV employees under the Contributory Provident Fund (CPF) were given only one opportunity to switch to the General Provident Fund (GPF) after the 4th Pay Commission in 1986. This has resulted in many retired teachers facing financial hardship in their old age. The second concern involves the health benefits under the Central Government Health Scheme (CGHS). Retired KV employees often encounter delays in the reimbursement of medical expenses, which are supposed to be covered on a cost-to-cost basis. These delays increase the financial strain on our senior citizens, who depend on timely access to healthcare funds. Thirdly, from the academic year 2022-23, the reservation for grandchildren of KV employees has been removed. These employees work in challenging conditions, including remote and Naxal-affected areas, often risking their safety. The reservation was a small yet significant acknowledgment of their sacrifices. In light of their contributions, I urge the Government to address these issues by allowing CPF to GPF conversion, ensuring timely CGHS reimbursements, and extending the reservation criteria. (ends)

Re: Need to construct an overbridge on NH-106 and NH-57 intersection at Simrahi Bazar in Supaul district, Bihar

श्री दिलेश्वर कामैत (सुपौल) : बिहार के सुपौल जिला अंतर्गत राघोपुर प्रखंड के सिमराही बाजार के मध्य होते हुए उत्तर से दक्षिण एन.एच 106 बीरपुर से बीहपुर तथा पूरब से पश्चिम 4 लेन एन.एच 57 (वर्तमान एन.एच 27) जाती है। उक्त सड़क के सिमराही चौराहे पर बराबर दुर्घटनाएँ होती रहती है एवं आवागमन भी बाधित हो जाती है तथा जान माल की भी काफी क्षति होती है I अतः जनहित में सदन के माध्यम से भारत सरकार के सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री जी से आग्रह है कि उक्त चौराहे पर रोड ओवर ब्रिज का निर्माण किया जाय I

(इति)

Re: Providing legal status to MSP for agriculture produce

SHRIMATI SUPRIYA SULE (BARAMATI): Our farmers have once again been forced to take to the streets to compel the Government to fulfil its promise of providing legal status to MSP for agriculture produce and they have been met with violence and harassment. Peaceful marches have been halted by barricades, tear gas shells, and roads lined with barbed wire and nails. The police have also resorted to underhanded tactics of creating fear and intimidation to suppress this movement, surrounding villages, forbidding farmers from leaving their homes, and threatening farmers, including the elderly and sick, with arrest if they choose to participate in it.

It is deeply regrettable that our farmers, who toil relentlessly to feed the nation, are being treated as adversaries by the state. The guarantee of MSP in the C2 + 50% formula as recommended by the Swaminathan Commission is long due, and will be the lifeline that revives our declining agriculture sector that has slumped over the last decade.

(ends)

Re: Six-laning of Nellore Chennai National Highway

SHRI MADDILA GURUMOORTHY (TIRUPATI): I would like to raise the growing traffic congestion on the National Highway connecting Nellore to Chennai, which currently operates as a 4-lane road. This highway has experienced a significant surge in traffic due to the heavy movement of goods from Krishnapatnam Port and industrial transport from Special Economic Zones (SEZs) such as Sri City and Menakuru. The 4-lane highway is now insufficient to handle this growing traffic, leading to severe congestion, delays, and a rise in accidents. It is essential to upgrade the highway to a 6-lane configuration to ensure smooth and safe vehicle movement. This expansion will alleviate traffic congestion, reduce travel time, and enhance logistical efficiency, benefiting industries in the region and contributing to economic growth. Hence, I request the Government to initiate the necessary steps for upgrading Nellore to Chennai highway from 4-lane to 6-lane to ensure the safety of commuters and promote industrial development.

(ends)

Re: Need to ensure adequate supply of DAP to farmers

श्री सुधाकर सिंह (बक्सर) : मैं आपका ध्यान एक अत्यंत महत्वपूर्ण मुद्दे की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ, जो किसानों के जीवन और रबी फसल की तैयारी से जुड़ा हुआ है। रबी सीजन की शुरुआत से पहले, हमारे किसानों को डीएपी खाद की भारी किल्लत का सामना करना पड़ रहा है।किसान देश की रीढ़ हैं, और उनकी समस्याओं का समाधान तत्काल होना चाहिए। मैं सरकार से आग्रह करता हूँ कि डीएपी खाद की आपूर्ति सुनिश्चित की जाए और उसकी उपलब्धता के लिए एक ठोस योजना तैयार की जाए। यह सुनिश्चित किया जाए कि किसानों को खाद लेने के लिए लंबी कतारों में खड़ा न होना पड़े। डीएपी की अनुपलब्धता से प्रभावित किसानों को वैकल्पिक खाद पर सब्सिडी प्रदान की जाए। ज़मीनी स्तर पर अधिकारियों की जवाबदेही तय की जाए ताकि किसानों को समय पर सहायता मिल सके। किसानों की इस समस्या को अनदेखा करना देश की खाद्य सुरक्षा को संकट में डाल सकता है। अतः सरकार को इस दिशा में तुरंत कदम उठाने चाहिए।

(इति)

Re: Need to earmark the un-utilized property of Parvathy Mills for establishment of new ESI Medical College at Kollam, Kerala

SHRI N. K. PREMACHANDRAN (KOLLAM): Parvathy Mills Kollam owned about 16.40 acres of prime land in the heart of Kollam City. The property is not being utilized by the Parvathy Mills or Textile Ministry. The non utilization of prime land has become a public issue. The request for revival of the Parvathy Mills is not considered by the Union Government. Transfer of the property to other Departments of Union Government or State Government also not materialized due to pendency of litigation. There is a proposal for ESI Medical College at Kollam. The land of Parvathy Mills is suitable for this. The pending litigation is a hurdle. It is highly necessary to initiate steps for speedy disposal of the litigation. Hence, I urge upon the Government to initiate urgent action for speedy disposal of the pending litigation regarding Parvathy Mills and earmark the property for new ESI Medical College at Kollam.

(ends)

… (व्यवधान)

माननीय सभापति : माननीय रेल मंत्री जी।

… (व्यवधान)

रेल (संशोधन) विधेयक – जारी

1401 बजे

रेल मंत्री; सूचना और प्रसारण मंत्री; तथा इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री अश्विनी वैष्णव) : माननीय सभापति महोदया, मैं आपको बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने इस सदन में रेलवे पर इतनी विस्तृत चर्चा करायी। 72 माननीय सदस्यों ने अपने विचार रखे, विषय को अच्छी तरह से रखा कि किस तरह से रेलवे का विकास हो। … (व्यवधान)

माननीय सभापति : माननीय रेल मंत्री जी रेलवे विधेयक पर रिप्लाई दे रहे हैं।

… (<u>व्यवधान</u>)

श्री अश्विनी वैष्णव : माननीय सभापति महोदया, रेलवे के विकास के लिए जितने भी सुझाव आए, उनके लिए मैं सभी माननीय सांसद महोदय को धन्यवाद देना चाहता हूं। … (व्यवधान)

माननीय सभापति : मैं सभी माननीय सदस्यों से आग्रह कर रही हूं, माननीय मंत्री जी रेलवे विधेयक पर रिप्लाई दे रहे हैं। आप सभी अपने-अपने स्थान पर बैठें।

… (<u>व्यवधान</u>)

माननीय सभापति : सदन की कार्यवाही तीन बजे के लिए स्थगित की जाती है।

1402 बजे

<u>तत्पश्चात् लोक सभा पन्द्रह बजे तक के लिए स्थगित हुई।</u>

(1500/SK/AK)

1500 बजे

लोक सभा पन्द्रह बजे पुनः समवेत् हुई।

(श्रीमती संध्या राय पीठासीन हुईं।)

…(व्यवधान)

माननीय सभापति: मैं सभी माननीय सदस्यों से आग्रह करती हूं कि सदन की कार्यवाही चलने दें। अब माननीय रेल मंत्री जी रिप्लाई देंगे।

… (व्यवधान)

माननीय सभापति: आप सबके सारे विषयों को सुना भी जा रहा है और सब विषयों पर चर्चा भी हुई।

… (व्यवधान)

माननीय सभापति: अगर सबकी सहमति हो तो माननीय रेल मिनिस्टर का रिप्लाई कराया जाए?

… (व्यवधान)

माननीय सभापति: मैं आप सबसे आग्रह कर रही हूं, पूरा देश सदन की कार्यवाही देख रहा है। माननीय रेल मंत्री जी का रिप्लाई आना है। अगर आप सबकी सहमति हो तो रिप्लाई कराया जाए?

… (व्यवधान)

माननीय सभापति : सदन की कार्यवाही मंगलवार दिनांक 10 दिसंबर, 2024 को प्रात: 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

1501 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा मंगलवार, 10 दिसम्बर 2024 / 19 अग्रहायण 1946 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।